बूदिरेड्डी चंद्रैया और अन्य

बनाम

अरिजेला लक्ष्मी और अन्य

सितम्बर 17, 2007

(डा. अरिजीत पासायट और डी.के. जैन, न्यायाधीश)

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 -

धारा 100-द्वितीय अपील-राज्य और उच्च न्यायालय को अपील का ज्ञापन विधि के सारवान प्रश्न पर विचार करने हेतु: सर्वोच्च न्यायालय के कई निर्णयों के बावजूद, द्वितीय अपील पर निर्णय लेने से पहले विधि के सारवान प्रश्न यदि कोई हो, तैयार करने की आवश्यकता का पालन नहीं किया जा रही है। फैसले में धारा 100 से संबंधित सिद्धांतों का सारांश दिया गया है। विधि का सारवान प्रश्न, यदि कोई हो, तैयार करने और तद्नुसार दूसरी अपील पर निर्णय लेने के लिए मामला उच्च न्यायालय को भेजा गया।

शब्दों और वाक्यांशों:

वाक्यांश ''विधि का सारवान प्रश्न'' और अभिव्यक्ति ''सारवान'' धारा 100 सी.पी.सी. के संदर्भ में।

त्वरित अपील में सी.पी.सी. की धारा 100 के संदर्भ में दूसरी अपील में उच्च न्यायालय के आक्षेपित फैसले की वैधता पर मुख्य रूप से इस आधार पर सवाल उठाया गया था कि विधि के किसी भी सारवान प्रश्न को तैयार किए बिना अपील की अनुमति दी गई थी।

कोर्ट ने अपील स्वीकार करते हुए अभिनिर्धारित किया:

इस न्यायालय के कई निर्णयों को उजागर करने के बावजूद दूसरी अपील पर निर्णय देने से पहले विधि के सारवान प्रश्न, यदि कोई हो, तैयार करने की अनिवार्य आवश्यकता का बार-बार पालन नहीं किया जा रहा है और, उच्च न्यायालय नोटिस जारी कर रहे हैं और आम तौर पर निर्धारित प्रक्रिया का पालन किए बिना दूसरी अपील पर निर्णय ले रहे हैं। सी.पी.सी. की धारा 100 के तहत संशोधन के बाद दूसरी अपील केवल तभी दायर की जा सकती है, जब मामले में विधि का कोई सारवान प्रश्न शामिल हो। अपील के ज्ञापन में शामिल कानून के महत्वपूर्ण प्रश्न का स्पष्ट रूप से उल्लेख होना चाहिए और उच्च न्यायालय ऐसे प्रश्न के अस्तित्व के संबंध में खुद को संतुष्ट करने के लिए बाध्य है। यह ध्यान में रखना होगा कि अपील का अधिकार मुकदमेबाजी से जुड़ा न तो प्राकृतिक और न ही अंतर्निहित अधिकार है। एक महत्वपूर्ण वैधानिक अधिकार होने के नाते, इसे प्रासंगिक समय पर लागू कानून के अनुसार विनियमित किया जाना चाहिए। दूसरी अपील जारी रखने से पहले धारा में उल्लिखित शर्तों को

सख्ती से पूरा किया जाना चाहिए और किसी भी अदालत को इसमें जोड़ने की शक्ति नहीं है या उन आधारों का विस्तार करना।

1.2 वाक्यांश ‘‘विधि का सारवान प्रश्न’’, -जैसा कि घटित होता है कि सी.पी.सी. की संशोधित धारा 100 को संहिता में परिभाषित नहीं किया गया है। पर्याप्त शब्द, ‘‘विधि के प्रश्न’’ के रूप में, का अर्थ है- सार, आवश्यक, वास्तविक, सार्थक, महत्वपूर्ण या विचारणीय होना। इसे किसी विरोधाभासी चीज के रूप् में समझा जाना चाहिए-तकनीकी, जिसका कोई सार या परिणाम नहीं है या केवल अकादमिक। ‘‘पर्याप्त’’ होने के लिए विधि का प्रश्न बहस योग्य होना चाहिए, पहले देश के कानून या बाध्यकारी मिसाल द्वारा तय नहीं किया जाना चाहिए और जहां तक अधिकारों का सवाल है, किसी भी तरह से उत्तर दिए जाने पर मामले के निर्णय पर इसका महत्वपूर्ण प्रभाव होना चाहिए। इससे पहले संबंधित पक्षों का संबंध है।

1.3 धारा 100 सी.पी.सी. से संबंधित सिद्धांतों को इस प्रकार संक्षेप में प्रस्तुत किया जा सकता है:

(i) किसी दस्तावेज की सामग्री के विवरण से तथ्य का अनुमान लगाना तथ्य का प्रश्न है, लेकिन किसी दस्तावेज की शर्तों का विधिक प्रभाव विधि का प्रश्न है। कानून के सिद्धांत के अनुप्रयोग से जुड़े दस्तावेज का निर्माण भी विधि का प्रश्न है। इसलिए, जब किसी दस्तावेज का गलत

निर्माण होता है या किसी दस्तावेज की व्याख्या करने में विधि के सिद्धांत का गलत अनुप्रयोग होता है, तो यह विधि के प्रश्न को जन्म देता है; (पप) उच्च न्यायालय को इस बात से संतुष्ट होना चाहिए कि मामले में कानून का एक महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल है, न कि केवल कानून का प्रश्न। कानून का कोई प्रश्न जसका मामले के निर्णय पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है (अर्थात् एक प्रश्न, जिसका उत्तर मुदकमें के पक्षकारों के अधिकारों को प्रभावित करता है) कानून का एक महत्वपूर्ण प्रश्न होगा, यदि यह किसी विशिष्ट प्रावधान के अंतर्गत नहीं आता है। कानून या बाध्यकारी से उभरे स्थापित कानूनी सिद्धांत मिसालें और इसमें एक बहस योग्य कानूनी मुद्दा शामिल है। कानून का एक महत्वपूर्ण प्रश्न एक विपरीत स्थिति में भी उठेगा, जहां कानूनी स्थिति स्पष्ट है या तो कानून के स्पष्ट प्रावधानों या बाध्यकारी उदाहरणों के कारण, लेकिन निचली अदालत ने या तो ऐसे कानूनी सिद्धांत की अनदेखी करते हुए या इसके विपरीत कार्य करते हुए मामले का फैसला किया है। दूसरे प्रकरण के मामलों में कानून का सारगर्भित प्रश्न, यह इसलिए नहीं उठता क्योंकि कानून अभी भी बहस योग्य है, बल्कि इसलिए कि किसी महत्वपूर्ण प्रश्न पर दिया गया निर्णय कानून की स्थापित स्थिति का उल्लंघन करता है।

सर चुन्नीलाल वी. मेहता एंड संस लिमिटेड बनाम सेंचुरी एस.पी.जी. एवं एम.एफ.जी. लिमिटेड, ए.आई.आर. (1962) एससी 1314; भारतीय

रिजर्व बैंक बनाम रामकृष्ण गोविंद मोरे, (1976) 1 एससीसी 803; कांेडीबा डोगाडु कदम बनाम सावित्रीबाई सोपान ग्वार और अन्य, (1999), 3 एससीसी 722; गुरान दित्ता बनाम टी. राम दित्ता, ए.आई.आर. (1928) पीसी 172; रिममलापुडी सुब्बा राव बनाम नूनी वीरजू, ए.आई.आर. (1951) मैड 969; उप. कमिश्नर हरदोइव बनाम राम कृष्ण नारायण, ए.आई.आर. बी(1953) एससी 521 और संतोष हजारी बनाम पुरूषोत्तम तिवारी (मृतक) एलआरएस द्वारा (2001) 3 एससीसी 179, पर भरोसा किया गया।

1.4 आक्षेपित आदेश को अपास्त किया जाता है और मामले को प्रेषित किया जाता है। उच्च न्यायालय कानून का महत्वपूर्ण प्रश्न, यदि कोई हो, तैयार करेगा और उसके बाद अपील पर निर्णय करेगा। यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि यदि इसमें कानून का कोई महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल नहीं है, तो अपील को खारिज कर दिया जाना चाहिए। (पैरा 15)

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: 2007 की सिविल अपील संख्या 4306

2002 की दूसरी अपील संख्या 617 में हैदराबाद स्थित आंध्रप्रदेश के उच्च न्यायालय के निर्णय और आदेश दिनांक 21.01.2003 से।

अपीलकर्ता की ओर से डी. रामकृष्ण रेड्डी और डी. भारती रेड्डी।

पी.एस. नरसिम्हा, के. मारुति राव, के. राधा और अंजनी अय्यागरी के लिए प्रतिवादी.

न्यायालय का निर्णय सुना गया

डाॅ. अरिजीत पसाया टी, न्यायाधीश

1. अनुमति दी गई।

2. अपीलकर्ता विद्वान निर्णय की वैधता पर प्रश्न उठाते है कि आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश ने नागरिक प्रक्रिया संहिता, 1908(संक्षेप में 'सी.पी.सी.') की धारा 100 के संदर्भ में उत्तरदाताओं द्वारा दायर दूसरी अपील की अनुमति दी। हालांकि अपील के समर्थन में कई बिंदुओं पर आग्रह किया गया था, मुख्य रूप से यह तर्क दिया गया था कि दूसरी अपील को कानून के किसी भी महत्वपूर्ण प्रश्न को तैयार किए बिना अनुमति दी गई थी, जो कानून में अनिवार्य है।

3. उत्तरदाताओं के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि यद्यपि कोई भी प्रश्न सही ढंग से तैयार नहीं किया गया है, लेकिन बुनियादी कारकों को ध्यान में रखा गया है और रिकाॅर्ड पर सामग्री पर विचार के बाद दूसरी अपील की अनुमति दी गई थी।

4. संशोधन के बाद दूसरी अपील केवल तभी दायर की जा सकती है जब मामले में कानून का कोई महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल हो। अपील के ज्ञापन में शामिल कानून के महत्वपूर्ण प्रश्न का स्पष्ट रूप से उल्लेख होना चाहिए और उच्च न्यायालय ऐसे प्रश्न के अस्तित्व के संबंध में खुद को संतुष्ट करने के लिए बाध्य है। संतुष्ट होने पर, उच्च न्यायालय को मामले

में शामिल कानून के महत्वपूर्ण प्रश्न तैयार करने होंगे। इस प्रकार तैयार किए गए प्रश्न पर अपील की सुनवाई आवश्यक है। हालांकि, अपील की सुनवाई के समय प्रतिवादी को यह तर्क देने का अधिकार है कि अदालत में मामले में कानून का कोई महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल नहीं था। धारा का प्रावधान कानून के एक महत्वपूर्ण बिंदु पर अपील सुनने के लिए उच्च न्यायालय की शक्तियों को स्वीकार करता है, हालांकि इसे यह सुनिश्चित करने के उद्देश्य से तैयार नहीं किया गया है कि वादी के साथ कोई अन्याय न हो जहां ऐसा प्रश्न तैयार नहीं किया गया था। प्रवेश का समय या तो गलती से या असावधानी से।

5. यह बार-बार नोट किया गया है कि बिना आग्रह किये अपील के ज्ञापन में कानून के ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न का विवरण और प्रवेश के समय इसे तैयार करने के बाद, उच्च न्यायालय नोटिस जारी कर रहे हैं और आम तौर पर सीपीसी की धारा 100 के तहत निर्धारित प्रक्रिया का पालन किए बिना दूसरी अपील पर निर्णय ले रहे हैं। कई मामलों में यह पाया गया है कि कानून के प्रश्न और कानून के महत्वपूर्ण प्रश्न के बीच अंतर करने का कोई प्रयास नहीं किया जाता है। कई मामलों में इस धारा के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए, प्रथम अपीलीय के तथ्य के निष्कर्ष अदालत में गड़बड़ी पाई गई है। यह ध्यान में रखना होगा कि अपील का अधिकार मुकदमेबाजी से जुड़ा न तो प्राकृतिक और न ही अंतर्निहित अधिकार है।

एक वास्तविक वैधानिक अधिकार होने के नाते इसे प्रासंगिक समय पर लागू कानून के अनुसार विनियमित किया जाना चाहिए। दूसरी अपील जारी रखने से पहले धारा में उल्लिखित शर्तों को सख्ती से पूरा किया जाना चाहिए और किसी भी अदालत के पास उन आधारों को जोड़ने या बढ़ाने की शक्ति नहीं है। दूसरी अपील का निर्णय केवल न्यायसंगत आधार पर नहीं किया जा सकता। इस धारा के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए उच्च न्यायालय द्वारा तथ्यों के समवर्ती निष्कर्षों से छेडछाड़ नहीं की जाएगी। इसके अलावा, कानून के एक महत्वपूर्ण प्रश्न को अलग करना होगा तथ्य के एक महत्वपूर्ण से यह न्यायालय सर चुन्नीलाला वी. मेहता एंड संस लिमिटेड बनाम सेंचुरी एसपीजी में। एंड एमएफजी. कंपनी लिमिटेड, एआईआर (1960) एससी 1314 ने माना कि:

> "यह निर्धारित करने के लिए उचित परीक्षण कि क्या कानून का कोई प्रश्न उठाया गया है मामले में पर्याप्त है, हमारी राय में, चाहे वह हो सामान्य सार्वजनिक महत्व या चाहे वह प्रत्यक्ष और पर्याप्त रूप से हो पार्टियों के अधिकारों को प्रभावित करता है और यदि ऐसा है तो क्या यह खुला है, प्रश्न इस अर्थ में कि इसका समाधान अंततः इस न्यायालय द्वारा या इसके द्वारा नहीं किया गया है प्रिवी काउंसिल या संघीय न्यायालय द्वारा या कठिनाई से मुक्त

नहीं है या वैकल्पिक विचारों पर चर्चा का आह्वान करता है। यदि प्रश्न उच्चतम न्यायालय द्वारा तय कर दिया गया है या प्रश्न निर्धारित करने में लागू होने वाले सामान्य सिद्धांत अच्छी तरह से तय हो गए हैं और उन सिद्धांतों को लागू करने का सवाल ही है या उठाया गया तर्क स्पष्ट रूप से बेतुका है तो यह प्रश्न एक महत्वपूर्ण प्रश्न नहीं होगा।''

6. पहली अपीलीय अदालत होने के नाते, अंतिम तथ्य अदालत द्वारा जिन आधारों पर निष्कर्ष निकाले गए थे, उनकी जांच करना उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में नहीं है। यह सच है कि निचली अपीलीय अदालत को आमतौर पर विश्वसनीयता के संबंध में ट्रायल कोई द्वारा स्वीकार किए गए गवाहों को खारिज नहीं करना चाहिए, लेकिन यहां तक कि जहां उसने ट्रायल कोर्ट द्वारा स्वीकार किए गए गवाहों को खारिज कर दिया है, वहीं दूसरी अपील में हस्तक्षेप करने का कोई आधार नहीं है जब ऐसा पाया जाता है कि अपीलीय अदालत ने ऐसा करने के लिए संतोषजनक कारण बताए हैं। ऐसे मामले में जहां परिस्थितियों के एक सेट से तथ्य के दो निष्कर्ष संभव हैं, निचली अपीलीय अदालत द्वारा निकाले गए निष्कर्ष पर दूसरी अपील में उच्च न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। कोई अन्य दृष्टिकोण अपनाने की अनुमति नहीं हैं। ऊंचा हालांकि, न्यायालय हस्तक्षेप करेगा जहां यह पाया जाएगा कि निचली अपीलीय

अदालत द्वारा निकाले गए निष्कर्ष गलत थे और लागू कानून के अनिवार्य प्रावधानों या शीर्ष अदालत द्वारा की गई घोषणाओं के आधार पर इसकी निर्धारित स्थिति के विपरीत थे या अस्वीकार्य पर आधारित थे। साक्ष्य या भौतिक साक्ष्य की अनदेखी करके पहुंचा गया।

7. कानून का जो सवाल उठाया गया है, उसे सारगर्भित नहीं माना जाएगा कानून का प्रश्न, यदि यह संबंधित उच्च न्यायालय की बड़ी पीठ या प्रिवी काउंसिल या संघीय न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पहले ही तय किया जा चुका है। जहां कानून के किसी बिंदु के लिए आवश्यक तथ्यों की वकालत नहीं की गई है, किसी वादी को दूसरी अपील में कानून के एक महत्वपूर्ण प्रश्न के रूप में उस प्रश्न को उठाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। केवल तथ्यों, दस्तावेजी सबूतों या प्रविष्टियों के अर्थ और दस्तावेजों की सामग्री की सराहना को कानून का एक बड़ा सवाल उठाने वाला नहीं माना जा सकता है। लेकिन ऐसा कहां पाया जाता है पहली अपीलीय अदालत ने उस क्षेत्राधिकार को मान लिया है, जो उसमें निहित नहीं है, इसे कानून का एक महत्वपूर्ण प्रश्न मानते हुए दूसरी अपील में फैसला सुनाया जा सकता है। जहां पहली अपीलीय अदालत को न्यायिक तरीके से अपने विवेक का प्रयोग करते हुए दिखाया गया है, इसे दूसरी अपील में हस्तक्षेप की आवश्यकता वाले कानून या प्रक्रिया की त्रुटि नहीं कहा जा सकता है। भारतीय रिजर्व बैंक बनाम रामकृष्ट गोविंद मोरे,

(1976) I एसीसी 803 में इस न्यायालय ने यह निर्धारित करने के लिए उचित परीक्षण के रूप में निम्नलिखित परीक्षण निर्धारित किया कि मामले में उठाया गया कानून का प्रश्न पर्याप्त है या नहीं:

> "यह निर्धारित करने के लिए उचित परीक्षण कि क्या कानून का कोई प्रश्न उठाया गया है मामले मे पर्याप्त है, हमारी राय में, चाहे वह हो सामान्य सार्वजनिक महत्व या चाहे वह प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप् से हो पार्टियों के
>
> अधिकारों को प्रभावित करता है और यदि ऐसा है तो क्या यह खुला है प्रश्न इस अर्थ में कि इसका समाधान अंततः इस न्यायालय द्वारा या इसके द्वारा नहीं किया गया है प्रिवी काउंसिल या संघीय न्यायालय द्वारा या
>
> कठिनाई से मुक्त नहीं है या वैकल्पिक विचारों पर चर्चा का आह्वान करता है। यदि प्रश्न सुलझ गया उच्चतम न्यायालय द्वारा या प्रश्न का निर्धारण करने में लागू होने वाले सामान्य सिद्धांत अच्छी तरह से तय किए गए हैं और यह एक मात्र प्रश्न है उन सिद्धांतों को लागू करने या उठाई गई दलील स्पष्ट रूप से बेतुकी है यह प्रश्न कानून का कोई महत्वपूर्ण प्रश्न नहीं होगा।"

10. उप में. कमिश्नर हरदोई बनाम राम कृष्ण नारायण, एआईआर

(1953) एससी 521 में यह भी माना गया कि पार्टियों के लिए महत्व के कानू का प्रश्न अपीलकर्ता को सीपीसी की (तत्कालीन) धारा 100 के तहत एक प्रमाण पत्र का अधिकार देने वाला कानून का एक महत्वपूर्ण प्रश्न था।

11. ''पर्याप्त'' होने के लिए कानून का प्रश्न बहस योग्य होना चाहिए, नहीं पहले देश के कानून या एक बाध्यकारी मिसाल द्वारा तय किया गया था और मामले के निर्णय पर इसका भौतिक प्रभाव होना चाहिए, यदि किसी भी तरह से उत्तर दिया गया हो, जहां तक संबंधित पक्षों के अधिकारों का संबंध है। ''मामले में शामिल'' कानून का प्रश्न होने के लिए सबसे पहले दलीलों में इसकी नींव रखी जानी चाहिए और यह प्रश्न अदालत द्वारा तथ्यों के स्थायी निष्कर्षों से सामने आना चाहिए और उस प्रश्न का निर्णय करना आवश्यक होना चाहिए मामले के न्यायसंगत और उचित निर्णय के लिए कानून का उच्च न्यायालय के समक्ष पहली बार उठाया गया एक बिल्कुल नया मुद्दा मामले में तब तक शामिल नहीं है, जब तक कि यह मामले की जड़ तक नहीं जाता है। इसलिए, यह प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करेगा कि कानून का प्रश्न महत्वपूर्ण है और मामले में शामिल है या नहीं; कुल मिलाकर सर्वोपरि सभी अनिवार्य आवश्यकता के बीच एक विवेकपूर्ण संतुलन बनाने की आवश्यकता पर विचार किया जा रहा है। (देखें: संतोष हजारी बनाम पुरूषोत्तम तिवारी (मृतक) लार्स द्वारा, (2001) 3 एससीसी 179)।

12. इस मामले के लिए प्रासंगिक धारा 100 सीपीसी से संबंधित सिद्धांत, इस प्रकार ग्रीष्मीकरण किया जा सकता है:-

(i) किसी दस्तावेज के विवरण या सामग्री से तथ्य का अनुमान तथ्य का प्रश्न है, लेकिन एक दस्तावेज के दसियों का कानूनी प्रभाव कानून का सवाल है, से जुड़े दस्तावेज का निर्माण कानून के किसी सिद्धांत को लागू करना भी कानून का प्रश्न है। इसलिए, जब किसी दस्तावेज का गलत निर्माण होता है या किसी दस्तावेज की व्याख्या करने में कानून के सिद्धांत का गलत अनुप्रयोग होता है, तो यह कानून के प्रश्न को जन्म देता है।

(ii) उच्च न्यायालय को इस बात से संतुष्ट होना चाहिए कि मामले में निम्नलिखित शामिल है, कानून का सारगर्भित प्रश्न, न कि केवल कानून का प्रश्न। ए के निर्णय पर कानूनी प्रभाव डालने का प्रश्न मामला (अर्थात् एक प्रश्न, जिसका उत्तर मुकदमे के पक्षकारों के अधिकारों को प्रभावित करता है) कानून का एक महत्वपूर्ण प्रश्न होगा, यदि यह कानून के किसी विशिष्ट प्रावधान या बाध्यकारी उदाहरणों से उभरे स्थापित कानूनी सिद्धांत द्वारा कवर नहीं किया गया है और इसमें एक बहस योग्य कानूनी मुद्दा शामिल है। कानून का एक महत्वपूर्ण प्रश्न एक विपरीत स्थिति में भी उठेगा, जहां कानूनी स्थिति स्पष्ट है या तो कानून के स्पष्ट प्रावधानों या बाध्यकारी उदाहरणों के कारण, लेकिन निचली अदालत ने या तो ऐसे कानूनी सिद्धांत की अनदेखी करते हुए या इसके विपरीत कार्य करते

हुए मामले का फैसला किया है। दूसरे प्रकार के मामलों में, कानून का महत्वपूर्ण प्रश्न इसलिए नहीं उठता क्योंकि कानून अभी भी बहस योग्य है, बल्कि इसलिए उठता है क्योंकि किसी भौतिक प्रश्न पर दिया गया निर्णय कानून की स्थापित स्थिति का उल्लंघन करता है।

13. सामान्य नियम यह है कि उच्च न्यायालय समवर्ती में हस्तक्षेप नहीं करेगा नीचे दिए गए न्यायालयों के निष्कर्ष लेकिन यह कोई पूर्ण नियम नहीं है। कुछ सर्वमान्य अपवाद ऐसे हैं जहां (i) पहले की अदालतों ने भौतिक साक्ष्यों को नजरअंदाज कर दिया है या बिना किसी साक्ष्य के आधार पर कार्रवाई की है; (ii) अदालतों ने कानून को गलत तरीके से लागू करके सिद्ध तथ्यों से गलत निष्कर्ष निकाले हैं; या (iii) अदालतों ने गलत तरीके से सबूत का बोझ डाला है। जब हम 'बिना सबूत के निर्णय' का उल्लेख करते हैं, तो यह न केवल उन मामलों को संदर्भित करता है, जहां साक्ष्य की पूरी कमी है, बल्कि ऐसे किसी भी मामले को भी संदर्भित करता है, जहां समग्र रूप से लिया गया साक्ष्य, उचित रूप से समर्थन करने में सक्षम नहीं है।

14. इस न्यायालय के कई निर्णयों के बावजूद, दूसरी अपील पर निर्णय लेने से पहले, कानून के महत्वपूर्ण प्रश्न, यदि कोई हो, को तैयार करने की आवश्यकता पर बार-बार प्रकाश डाला गया है, यह हमारे ध्यान में आया है कि अनिवार्य आवश्यकता का पालन नहीं किया जा रहा है।

15. आक्षेपित आदेश को अपास्त किया जाता है और मामले को प्रेषित किया जाता है उच्च न्यायालय कानून का महत्वपूर्ण प्रश्न यदि कोई हो, तैयार करेगा और उसके बाद अपील पर निर्णय करेगा। यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि यदि कानून का कोई महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल नहीं है, तो अपील खारिज कर दी जानी चाहिए। हम यह स्पष्ट करते हैं कि हमने इस बारे में कोई विचार व्यक्त किया है कि क्या इसमें कानून का कोई महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल है।

16. अपील स्वीकार की जाती है। लागत के रूप में कोई आदेश नहीं किया जाएगा।

अपील की अनुमति दी गई।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल '**सुवास**' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी मीनाक्षी चौधरी (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।